उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, डॉक्टर का ट्रांसफर वहाँ से दूसरे अस्पताल में हो जाता है, लेकिन उसमें कभी भी कन्विक्शन नहीं होता है, न ही दोषियों को दंड दिया जाता है। इसके लिए कोई मेडिकल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए - जैसे तमाम अन्य सेवाओं में ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वैसा ही एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। इसमें पेशेंट का भी पक्ष सुना जाए और डॉक्टर का भी पक्ष सुना जाए। उस ट्रिब्यूनल में स्पेशलिस्ट भी होंगे और यदि किसी डॉक्टर का कोई कृत्य निंदनीय है, तो उसको दंडित किया जाए। अगर डॉक्टर निर्दोष होगा, तो एक्सपर्ट के माध्यम से सारी सच्चाई सामने आ सकेगी। मैं समझता हूं कि इससे डॉक्टर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और वे ज्यादा मनोयोग के साथ अपना काम कर सकेंगे।

मान्यवर, तमाम ऐसे आकस्मिक अवसर भी आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स अनेक तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। एक्सिडेंट के समय डॉक्टर एक्सिडेंट को झेलने का काम करता है, यदि डेथ हो जाती है, तो उन परिस्थितियों को भी हैंडल करने का काम करता है। मान्यवर, तमाम ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिनसे डॉक्टर जूझता है, लेकिन डॉक्टर की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से यह अपील करना चाहता हूं कि सरकार देश के उन 25 लाख से अधिक चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा विधेयक लेकर आए, जिससे वे सुरक्षित हो सकें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, .. (**समय की घंटी**).. मेरी इनसे भी प्रार्थना है कि कोई ऐसा विधेयक लाएं, जिससे वे सुरक्षित हो सकें। मान्यवर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Ashok Bajpai: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Harnath Singh Yadav (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Pabitra Margherita (Assam), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal) and Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh).

Issue of drought and floods in various states including Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, etc.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I wish to raise a matter of utmost importance to the people of Karnataka and the neighbouring States. Karnataka is currently grappling with one of the most severe droughts in the last 123 years. A staggering 223 out of the total 226 talukas in the State have been adversely affected by these drought conditions. Among these, 196 talukas are experiencing

severe consequences while 27 talukas face moderate effects.The damage to crops ranges from 40 per cent to 90 per cent in many cases. Total estimated loss due to crop damage in the State of Karnataka is pegged at Rs.35,162.05 crore. Compounding the severity of the situation, Karnataka is confronting a new challenge referred to as "green drought", where crops have matured, yet there is no yield.

In response to this critical situation, the State Government has sought assistance amounting to Rs.18,171.44 crores from the National Disaster Response Fund (NDRF). This financial support is crucial for providing input subsidies, gratuitous relief, and implementing other immediate drought relief measures. Due to low rainfall, water in various reservoirs is also at an alarmingly low level. The water storage is at its lowest in the last 5 years. Going forward, the State will also see shortage of drinking water for cattle and people. Thus, the Government should realize the precariousness of the situation. Under MGNREGA, the State has already achieved 98.16 per cent of its target of person-days generated for this year. The State Government has also requested for an increase in number of working days from 100 to 150 days. ...(*Time-bell rings.*)...

श्री उपसभापति : आपका टाइम खत्म हो गया है। 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली माइक बंद हो जाता है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The Karnataka Government has released various amounts from its own funds to provide immediate relief and assistance to the people of the State. The Government has taken several decisions to help farmers and people in the State including crop damage.

Sir, though my time is still left...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is already finished.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I request you because not only there is drought in some areas but the flood is also serious in Chennai particularly, Kerala and other places, and Vidarbha is also suffering from drought in various places. But the funds from the Central Government are not going there. Though the Chief Ministers are coming and requesting but the BJP Government is not taking any interest because they have won the elections. That is why I think that people are fully supporting them but they are not ready to redress their sufferings. Therefore, through you, I request them to please respond to these points and release the necessary funds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge: Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Syed Nasir Hussain (Karnataka), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Binoy Viswam (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Dr. Ashok Kumar Mittal, 'Concern over rising cases of Human Trafficking.' Not present. *...(Interruptions)...* Those who associate, please send your names here. Now, Shrimati Seema Dwivedi, 'Issue of wild animals damaging the agricultural crops in Uttar Pradesh.'

Issue of wild animals damaging the agricultural crops in Uttar Pradesh

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं किसानों से जुड़ी समस्या को सदन में रखना चाहती हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर प्रायः किसान अपना जीविकोपार्जन खेती के माध्यम से करते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसके लिए किसान सम्मान निधि योजना, किसान ट्रैक्टर योजना, किसान मित्र योजना, प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि योजनाएँ चल रही हैं। प्रदेश सरकार भी गाँव-गाँव में पशुशाला खोल कर पशुओं को रोकने का एक अच्छा कार्यक्रम लागू कर रही है। महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयाग, सुल्तानपुर जैसे हमारे तमाम जिले ऐसे हैं, जो बिल्कुल नदी के किनारे बसे हैं। वहाँ पर आवारा पशुओं, जैसे नीलगाय, जंगली सूअर आदि का इतना आतंक है कि उनसे किसानों की फसलें भारी मात्रा में बर्बाद हो रही हैं।

महोदय, मेरा अपना मानना है कि सरकार तो नियम बना रही है, सरकार का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जन-सहभागिता होनी भी जरूरी है। लोग अपने पशुओं को छुट्टा भी छोड़ देते हैं, जो खेतों में जाकर फसलों को बर्बाद करते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे जो जंगली जानवर हैं, इनकी रोकथाम के लिए और जन-सहभागिता बने, क्योंकि जन-सहयोग की भी इसमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी कोई ऐसा ठोस कानून बनाया जाए, ताकि लोग अपने पशुओं को छुट्टा नहीं छोड़ें।

मान्यवर, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूँगी कि हमारे किसान बड़े परिश्रम के साथ अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में आलू, गन्ना, गेहूँ, धान, अरहर की